



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]
No. 398]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2008/चैत्र 5, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2008/CHAITRA 5, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2008

का.आ. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का. आ. 1372, तारीख 14 दिसम्बर, 2004 द्वारा राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का 31 जनवरी, 2005 की अवधि तक अथवा नया प्राधिकरण का पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, गठन किया था।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 जनवरी, 2008 अथवा नए प्राधिकरण के पुनर्गठन तक जो पहले हो, अवधि के लिए पुनर्गठन करती है, प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

1. सचिव, —अध्यक्ष
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
नई दिल्ली
2. डा. पी. सान्याल, —सदस्य
विजिटिंग प्रोफेसर, स्कूल
आफ ओशनोग्राफिक
स्टडीज, जादवपुर विश्वविद्यालय,
कोलकाता -700029

3. मुख्य नगर नियोजक —सदस्य
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय,
पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली
4. सदस्य अथवा समतुल्य पक्ति —सदस्य
का अधिकारी केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड,
नई दिल्ली
5. महानिदेशक (पर्यटक) या —सदस्य
उसका प्रतिनिधि, पर्यटन
मंत्रालय, नई दिल्ली
6. निदेशक —सदस्य
केन्द्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान,
कोचीन
7. सदस्य अथवा समतुल्य पक्ति का —सदस्य
अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
8. डॉ. शैलेश नायक —सदस्य
निदेशक
आई एन सी ओ आई एस,
समुद्र विकास विभाग,
ओशन वैली, पोस्ट बक्स नं. 21,
आई डी ए जी डी मितला, पो. ओ.
हैदराबाद-500055
9. प्रो. एस रामचन्द्रन —सदस्य
उप कुलपति, भद्रास विश्वविद्यालय
चिपोक, चेन्नई- 600005

10. डॉ. एस. बाबा —सदस्य
निदेशक,
भूमि विज्ञान अध्ययन केन्द्र
अक्कुलम, तिरुवन्नंतपुरम-695031
11. श्री आर आनंद कुमार, —सदस्य
सलाहकार (सेवानिवृत्त),
पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, डीजी-II/109बी,
विकास पुरी, नई दिल्ली
12. अपर निदेशक या समतुल्य पंक्ति —सदस्य सचिव
का अधिकारी (प्रभाव मूल्यांकन)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण करने और उसमें सुधार करने तथा तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात्:-

- (i) उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों का समन्वय ।
- (ii) राज्य तटीय जोन प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन अथवा उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उसके लिए केन्द्र सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।
- (iii) (क) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों को उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक समझा जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना ।
(ख) (iii)(क) मामलों का स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करना ।
- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (iii) (क) के अधीन जारी किए गए निदेश के अनुपालन की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना; और
- (v) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i), (ii) और (iii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III. प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, और अन्य संस्थाओं को तकनीकी सहायता देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा यदि तटीय पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार से संबंधित विषय में यह आवश्यक हो ।

IV. प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यक क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध जोन, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ।

V. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में केन्द्र सरकार की नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केन्द्र स्थापित करना और उन्हें धन उपलब्ध कराने में सलाह दे सकेगा ।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित स्थापित पर्यावरणीय मुद्दों का निपटान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए।

VII. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट छः मास में कम से कम एक बार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियाँ और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन के अधीन होंगे।

IX. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

X. इस प्रकार पुनर्गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधि कारिता के अंतर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट किसी विषयों का संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आई ए-III]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2008

S.O.692(E).— Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1372(E), dated the 14th December, 2004, the Central Government constituted the National Coastal Zone Management Authority for a period upto 31st January, 2005 or till the new Authority is reconstituted, whichever is later;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons with effect from the date of publication of this Order to the 31st December, 2008, namely:—

1. Secretary, —Chairperson
Ministry of Environment and
Forests, New Delhi
2. Dr. P. Sanyal, —Member
Visiting Professor,
School of Oceanographic
Studies, Jadavpur University,
Kolkata-700029
3. Chief Town Planner, —Member
Ministry of Urban Affairs
and Employment, Department
of Environment, New Delhi

- | | |
|--|---------------------|
| 4. Member or an Officer of an equivalent rank, Central Groundwater Board, New Delhi | —Member |
| 5. Director General (Tourism) or his representative, Ministry of Tourism, New Delhi | —Member |
| 6. Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin | —Member |
| 7. Member or an Officer of equivalent rank, Central Water Commission, New Delhi | —Member |
| 8. Dr. Shailesh Nayak, Director, INCOIS, Department of Ocean Development, Ocean Valley, Post Box No.21, IDA-GD Mitla, P.O., Hyderabad-500055 | —Member |
| 9. Prof. S. Ramachandran, Vice Chancellor, University of Madras, Chepauk, Chennai-600005 | —Member |
| 10. Dr. M. Baba, Director, Centre for Earth Science Studies, Akkulam, Thiruvananthapuram - 695031 | —Member |
| 11. Shri R. Anandakumar, Advisor (Retd.), Ministry of Environment and Forests, DG-II/109B, Vikas Puri, New Delhi-18 | —Member |
| 12. Additional Director/Officer of an equivalent rank, (Impact Assessment), Ministry of Environment and Forests, New Delhi | —Member - Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas, namely:—

- (i) co-ordination of actions by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act;
- (ii) examination of the proposals for changes and modifications in classification of coastal zone areas and in the coastal zone management plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities and making specific

recommendations to the Central Government therefor;

- (iii) (a) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, issue directions under Section 5 of the said Act; (b) review of cases under sub-paragraph (iii) (a) either *suo moto*, or on the basis of complaint made by an individual or a representative body, or an organization functioning in the field of environment;
- (iv) file complaints, under Section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (iii) (a); and
- (v) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i), (ii) and (iii).

III. The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union Territory Governments or Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union Territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions or organisations as may be found necessary, in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment.

IV. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated coastal zone management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities.

V. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centres of excellence and funding, in matters relating to coastal regulation zone management.

VI. The Authority shall deal with all environmental issues relating to coastal regulation zone which may be referred to it by the Central Government.

VII. The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government.

VIII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

IX. The Authority shall have its headquarters at New Delhi.

X. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so reconstituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/18/1996-1A-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'